

3



एम्स के डॉ. सुनील चौहान एपीपीआईकॉन

4



प्रियंका गांधी ने किया संसद में दमदार प्रवेश

5



जयंत नाहटा ने बदली तकदीर और तस्वीर

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 32

शनि सोमवार, 16 दिसंबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पहला साल है बेमिसाल

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

...पर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा की अवैध तसल्ली और गुंडागर्दी से साय सरकार की हो रही फजीहत, केंद्र सरकार ने भी जताई आपत्ति



विजय शर्मा को जल्द ही किया जा सकता है मंत्री पद से बेदखल

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने कितने दिनों अपनी सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। ख़ास बात यह है कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में विष्णुदेव साय ने न सिर्फ़ किसी एक वर्ष को बरिफ़ सलाज के हर वर्ष के लिये जलजलित की योजनाएँ लक़्क़ु कि और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये योजनाबद्ध ढंग से कार्य भी किया। लेकिन एक कलकल है कि एक जलजली पूरे ललाब को ग़ात कर देती है। साय कैबिनेट के प्रमुख मंत्री और प्रदेश के गृहमंत्री पद पर विजय शर्मा की उदासीन कार्यशैली और उजड़ रहेये से प्रदेश सरकार की छवि को धुलिल करने से कहीं से कहीं तक कोई कलकल नहीं छोड़ी। एक तरफ़ जलक विष्णुदेव साय ललाबतर जलकलक्षण की दिशा में कार्य करने के लिये योजनाएँ बना रहे हैं वहीं, दूसरी तरफ़ विजय शर्मा ने गुंडागर्दी का ललात धरयव उठाते हुए बेधुलक टोलकर, वसुली, गुंडागर्दी जैसे हरकतों को अलाककर राज्य सरकार की लक़क को नज़र कर रख है। अदरयव करने वाली बात यह है कि विजय शर्मा की दिना परिदिना बहती इन हरकतों का खलकिलकन पूरी प्रदेश सरकार को गुंडागर्दी पर रख है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलसे हुए भी विजय शर्मा को टोक नहीं पा रहे हैं। **विस्तृत कवर स्टोरी पेज 2 पर...**

मध्यप्रदेश में

मोहन सरकार के कार्यकाल का एक साल

कामकाज बेहतर,

लेकिन कर्ज के भरोसे चल रही मोहन सरकार



-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार का एक साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी इस एक साल को 'स्वर्णिम कार्यकाल' बता कर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। लेकिन देखने में लग रहा है कि मोहन सरकार भी पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की भांति कर्ज पर चल रही है। सरकार पर बजट से ज्यादा कर्ज लद गया है। जिसका ही नतीजा है कि आज प्रदेश में ब्याज पर ही हजारों करोड़ रुपये अदा किये जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि सरकार ने ऐसा कोई सा महीना नहीं छोड़ा जब कर्ज न रिलिया हो। आय से ज्यादा गुज्य में खर्च है। कर्ज का बोझ बढ़ा है। लगातार कर्ज लेने का नतीजा यह है कि बजट से ज्यादा कर्ज हो गया है। कर्ज का बोझ कम करने के उपाय खोजे जा रहे हैं। सरकार में फिज़ूलखर्ची पर रोक लगाई गई है, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे। इस एक साल में मोहन सरकार ने भले ही कई उपलब्धियाँ हासिल की हो, अनेक क्षेत्रों में सरकार ने प्रगति की है लेकिन सवाल यहाँ है कि सरकार कर्ज के भरोसे कब तक

चलेगी। डॉ. मोहन यादव ने जब सत्ता संभाली थी, तब बजट से ज्यादा कर्ज का बोझ था। एक साल में सरकार ने खताने की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। स्थिति सुधरी थी, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ा है। यह 3.77 लाख करोड़ तक जा पहुँचा है। सप्लीमेंट्री बजट तक के हलाल हो गए हैं। ज्ञात रहे कि 2024-25 के लिए करीब 5.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। यह बीते वर्षों की तुलना में करीब 16% ज्यादा था। बढ़ता कर्ज आर्थिक सेहत सुधारने के प्रयास में नाकामी है। यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें विरासत में कई लाख करोड़ का कर्ज मिला। मध्य प्रदेश पर 3.85 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह उनके लिए बड़ी चुनौती है। औद्योगिकीकरण और शहरी विकास से पैसा तो आया लेकिन इसमें समय लगेगा।

इसके साथ ही प्रदेश का विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे 'विकलताओं से भरा साल' कया देकर सरकार पर आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 साल के कार्यकाल पर संतोष जताते हुए कहा, "सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए कानूनी कार्य किए हैं। (शेष पेज 2 पर)

एमएस भोपाल के डॉ. सुनील चौहान ने एपीपीआईकॉन-2024 में न्यूरोफिजियोलॉजी में अपने उत्कृष्ट योगदान से संस्थान का मान बढ़ाया



-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. भोपाल। एमएस भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में फिजियोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. सुनील चौहान ने एपीपीआईकॉन-2024 सम्मेलन में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई। यह सम्मेलन चेन्नई स्थित इंसआईटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयोजित किया गया था। डॉ. चौहान ने सम्मेलन में दोहरी भूमिका निभाई—फैकल्टी सदस्य और प्रस्तुतकर्ता के रूप में। उन्होंने सम्मेलन में एच रिफ्लेक्स और रिपीटेडिव नर्व स्टिम्यूलेशन (आरएफएस) जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोफिजियोलॉजिकल तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। एच-रिफ्लेक्स एक तकनीक है जिसका उपयोग रीढ़ की हड्डी के कार्यात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से संबन्धी और मोटर मार्गों के आकलन में मददगार है। इस प्रक्रिया में एक परिष्कृत तंत्रिका को स्टिम्युलेट किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप मांसपेशी प्रतिक्रिया को मापा जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र की सेहत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रिपीटेडिव स्टिम्यूलेशन टेस्ट का

उपयोग आमतौर पर म्यूस्युथिनिया ग्रेविस जैसे न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन विकारों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण यह समझने में मदद करता है कि बार-बार की तंत्रिका स्टिम्यूलेशन के दौरान तंत्रिका संकेत मांसपेशियों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने किया और इसमें भारत व विदेशों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भाग लिया। डॉ. चौहान के योगदान पर प्रकाश डालते हुए, प्रो. सिंह ने कहा, "एपीपीआईकॉन-2024 जैसे प्रतिष्ठित सम्मेलनों में भागीदारी एमएस भोपाल की चिकित्सा ज्ञान और रोगी देखभाल को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डॉ. सुनील चौहान के द्वारा किए गए प्रशिक्षण और शोध प्रस्तुतियों संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति समर्पण को उजागर करती हैं। उनका कार्य न केवल न्यूरोफिजियोलॉजी के मानकों को ऊंचा उठाता है, बल्कि दूसरों को भी वैज्ञानिक अनुसंधान और नैदानिक उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है।" एपीपीआईकॉन-2024 अकादमिक चर्चा, पेशेवर नेटवर्किंग और न्यूरोफिजियोलॉजी में नवीनतम प्रगति साझा करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच साबित हुआ। (जगत फीचर्स)

सभी अधिकारी सुनिश्चित करें जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे: कलेक्टर

-नेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नरसिंघपुर। जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर ने समय स्वीमा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने सभी नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत के सीओ को निर्देशित किया कि वे अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएं। प्रत्येक गांव, मोहल्ले और कॉलोनी में जाकर लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करें। इसके साथ ही, हित प्राप्ति के आवेदन फॉर्म भी इस दौरान प्राप्त किये जायें। अभियान के दौरान विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाए तथा इन शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रह कर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान का प्रयास करें। साथ ही, पात्र हितप्राप्ति के आवेदन फॉर्मों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया को तेजी से किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस अभियान को पूरी गंभीरता से लें और इसे सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। बैठक में उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे विभागीय योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर सोनिया मीना ने बैठक के दौरान जिले के सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे धरती अन्ना अभियान के तहत चिन्हित 83 ग्रामों में मूल्यांकन सुविधाओं के विकास के लिए तत्काल कार्यवाही करें। (जगत फीचर्स)

तुम्हारा मौन कहीं पैदा न कर दे गाइडवारा में दुर्लभ कश्यप..!

-वद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंघपुर। दुर्लभ कश्यप और उसके करनामों से कंपने वाला उज्जैन शहर और समूचा मध्यप्रदेश आज भी दुर्लभ कश्यप के नाम थरथराता है। दुर्लभ का अंत तो 2020 में ही हो गया लेकिन गाइडवारा शहर में बीते दिनों हुए मधुर चौरसिया नरसंहार का दुर्लभ ने शहर में दाशत का माहौल खड़ा कर दिया है। बहुत अपराध में शहर के लोगों की बड़ती चुपचाप शहर के बाशियों को कहीं दूसरा दुर्लभ कश्यप न दे दे। दुर्लभ कश्यप इसलिए कि आंशों के शहर में हुई इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों के मुँह पर लगे तांतों ने मानवीयता पर लग रहे हास को बचा कर दिया है। शहर के बीचों बीच थिक रही अवैध शावक, शहर में बड़ता

स्मैक का नशा, साहूकारों का चक्रवर्ती व्याज, अपराधियों का खुलेआम अपराध करना कल मधुर चौरसिया पर बीता तो कहीं कल आंके धरों से कोई मधुर देखने न मिले इसीलिए विरोध जरूरी है। शहरवासियों की चुपियों ने उस परिवार को अकेला छोड़ दिया और वे बताया कि उन्हें भी अपने शहर गाइडवारा में उज्जैनी दुर्लभ कश्यप की जरूरत है। न सता न विषम, सिवाय मीडिया के किसी ने इस घटनाक्रम पर खुलकर विरोध नहीं किया। जबकि शहर बंद होना था एकमत विरोध होकर आसफिक काम बंद होने थे। पुलिस ने कार्यवाही की लेकिन उस रिक्तपद को कचरे में डालकर पुलिस ने बता दिया कि बिना घटना घटित हुए पुलिस केवल तमपरावीन बनी रहने के लिए है। (जगत फीचर्स)

खराब पोषण आहार पर कार्यवाही

-प्रमोद वरसले

जगत प्रवाह. टिम्बरनी। टिम्बरनी के आंगनवाड़ी केंद्रों में घंटिया पोषण आहार वितरित किया प्रारंभ न कड़ा कदम उठाते हुए मां रखा स्व सहायता समूह का कार्य आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला बाल विकास संजय त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश पर यह कार्यवाही की है। आंगनवाड़ी केंद्रों में मीनू अनुसार भोजे गू चावल में कोई निकले। विधायक प्रतिनिधि श्रीमती सोलंकी नगर परिषद विधायक प्रतिनिधि ओमप्रकाश मिश्रा ने वार्ड 4 में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्रों पर मीनू अनुसार भोजे गू चावल में कोई निकले। नगर की 19 आंगनवाड़ी केंद्रों में उस समय सभी अर्चिपत रह गये जब बच्चों को मीनू अनुसार चावल में कोई निकले। प्राय जानकारी के अनुसार मीनू के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों में पुराव कड़ी फकते दिये जाते हैं। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों ने ब्यावर से वैकल्पिक व्यवस्था कर बच्चों को भोजन कराया। वहीं कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों ने खाना हटवाया। यह बात आग को तरह पूरी टिम्बरनी में फैल गई। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों से खाना हटवाया गया। जब यह जानकारी मिली तो महिला बाल विकास विभाग विधायक प्रतिनिधि श्रीमती रितु सोलंकी एवं नगर परिषद विधायक प्रतिनिधि ओमप्रकाश मिश्रा ने वार्ड 4 की आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया जो शिकायत आई है वह सत्य है। आंगनवाड़ी केंद्र में आभ भोजन को देखा जिसमें कोई नजर आये। फिर दोनों ने पंचनामा बनाया। टिम्बरनी शहरी स्कूलों में मध्यम भोजन पदक कर रहे 5 स्व सहायता समूह को नवीन व्यवस्था होने तक टिम्बरनी शहर की 19 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार पदय करने का काय दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास हरदा संजय त्रिपाठी ने बताया कि जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में पोषण आहार पदय करने हेतु नवीन स्व सहायता समूह के चयन की कार्यवाही की जा रही है। (जगत फीचर्स)



पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने पुलिस लाईन में आयोजित जनरल परेड की सलामी ली

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के द्वारा सभी पुलिस इकाईयों में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को नियमित रूप से जनरल परेड आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी ने पुलिस लाईन में आयोजित जनरल परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विदिशा के द्वारा परेड का बारीकी से निरीक्षण किया तथा अर्च्य टर्नआउट वाले 16 अधिकारी/कर्मचारियों को पुरुस्कृत किया। साथ ही पुलिस बैण्ड का भी निरीक्षण किया गया। जनरल परेड के दौरान स्काई ड्रिल, बन्वा परेड एवं ओआर का आयोजन भी किया गया। पुलिस



अधीक्षक विदिशा द्वारा थाना स्तर पर अर्च्य कार्य करने वाले 11 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किये। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मजबूती मिलती है और शास्त्र कवायत के कौशल में सुधार होता है। परेड के माध्यम से पुलिस कर्मियों की नियमित फिटनेस बेहतर होती है और यह पुलिस अधिकारियों और जवानों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने का माध्यम बनती है। जनरल परेड के दौरान प्रमुख रूप से अनुविभागीय अधीक्षक पुलिस सिराज उमेश तिवारी, अनुविभागीय अधीक्षक पुलिस लटेरी अजय मिश्रा, अनुविभागीय अधीक्षक पुलिस गंजबासोदा मनोज मिश्रा, अनुविभागीय अधीक्षक पुलिस कुरवाई मनीष राज, भूर सिंह चौहान रहित निरीक्षक विदिशा विदिशा ने बताया गया कि जनरल परेड का नियमित आय्यास करने से जवानों में एकता और अनुशासन की भावना को

सहित जिले के सभी थाना प्रभारी सहित लगभग 120 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। (जगत फीचर्स)

समूह नृत्य में मिला तृतीय स्थान



-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। भारतीय ज्ञान परम्परा पर आयोजित जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में शसकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरी की समूह नृत्य टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आयोजित कार्यक्रम में जिले की 13 टीमों ने सहभागिता की जिसमें देवरी महाविद्यालय की टीम ने बधाई नृत्य प्रस्तुत करते भारतीय ज्ञान परम्परा को जीवंत करने का प्रयास मंच के माध्यम से किया। इस अवसर पर दल प्रभारी डॉ. मनीषा पाण्डे एवं टीम कु. वैशाली रजक, कु. नृपानु बाल्मीक, कु. आफरीन, अरमान बहाना, अक्षय पाण्डेय, कु. कल्पना काहार को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश दुबे एवं जनभागीदारी अध्यक्ष दीपक ठाकुर द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि आप और छात्र-छात्राएं बधाई के पात्र हैं जिन्होंने महाविद्यालय एवं नगर का नाम रोशन किया। इस अवसर पर डॉ. जी.आर. चौहान, डॉ. मनोज कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। (जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

बांग्लादेश के बाद पश्चिम बंगाल में क्यों बन रही अराजक स्थितियां ?

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलमूल रवैए, तुणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और कट्टरवादी ताकतों की निर्भय सक्रियता के कारण अराजक स्थितियां बन गई हैं। सत्ताधारी दल, उसकी विचारधारा और अन्य मामलों में असहमति रखनेवाले नागरिकों के लिए वहाँ जीवनयापन अत्यंत कठिन हो गया है। पश्चिम बंगाल से कई बीडियों वायरल हुए हैं, जिनमें विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को मारापीटा जा रहा है। यहाँ तक की इस्लामिक कानूनों को आधार बनाकर शरिया अदालतें लगाई जा रही हैं और लोगों को सजा दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो इस स्थिति की ओर समूचे देश का ध्यान आकर्षित किया ही जा रहा था लेकिन अब प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक उनकी चिंता के साथ अपना समर्थन प्रदर्शित नहीं किया है। क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश की भयावह स्थितियों पर अब तक चुप है। जबकि पश्चिम बंगाल में तुणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं मुस्लिम गुंडों को आर से केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं की ही मारपीट एवं हत्या नहीं की जा रही है अपितु उनके निशाने पर वामपंथी और कांग्रेसी कार्यकर्ता, समर्थक भी हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ता की पेड़ से बांधकर पीट-पीटकर हत्या की दी गई। लेकिन अभी तक अधीर रंजन चौधरी के अलावा किसी भी कांग्रेसी नेता की संवेदनशील नहीं जागी है।

संभवतः कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी को बनाए रखने की मंशा से 'जंगल राज' और अपने कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाओं में चुप्पी साधने को मजबूर है। लेकिन ऐसी मजबूरी किसी काम की जो लोकतंत्र और संविधान

की रक्षा ही नहीं कर सके। अपने कार्यकर्ताओं के दुःख-दर्द में सहभागी न हो सके। प्रदेश में स्थितियां इतनी भयावह हैं कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में बनी अराजक स्थिति से राष्ट्रपति को अवगत कराया और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने उन सब बातों को दोहराया है, जिन्हें अब तक भाजपा उठाती आई है। जैसे, चुनावी एवं राजनीतिक हिंसा। पंचायत एवं विधानसभा चुनावों की भीति हाल ही में सम्पन्न हुए आम चुनावों के दौरान एवं बाद में तुणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करना, उनकी आजीविका समाप्त करना और भ्रूवीकरण करना। दो पत्रों के पत्र में चौधरी ने स्पष्ट लिखा कि "मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर, राज्य में अराजक स्थिति को देखना न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि बहुत पीड़ादायक भी है। इसका कारण सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्ष के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों के प्रति क्रूर रवैया है"। चौधरी ने 'क्रूर रवैया' शब्द का उपयोग उचित ही किया है। जिस प्रकार से वहाँ लोगों के घर-दुकान जलाए जा रहे हैं, उनको घेरकर निर्दयीयता के साथ मारा-पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, यह सब क्रूरता की पराकाष्ठा है। इस क्रूरता के कारण लोगों को अपने घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी उम्मीद तो कम ही है कि अधीर रंजन चौधरी की पीड़ा को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुनेगा। परंतु, पश्चिम बंगाल की स्थितियां सुधारने एवं कानून की व्यवस्था लागू कराने के लिए केंद्र सरकार को अवश्य ही कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

सियासी गहमागहमी

कौन बनेगा मध्यप्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष?



मध्यप्रदेश में भाजपा में इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर खासी गहमागहमी मची हुई है। हर कोई इस सवाल का जवाब खूंदने में जुटा हुआ है कि आखिर प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। एक तरफ जहाँ भूपेन्द्र सिंह के नाम की चर्चा तेज है, वहीं दूसरी ओर बीडी शर्मा अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर पूरा गणित बैटाने में जुटे हुए हैं। इस बीच एक और नया नाम आया है वह है प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का। ऐसे में अगर भाजपा शीर्ष नेतृत्व जातिवाद के गणित को बैठाता है तो फिर नरोत्तम मिश्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के संकेत अधिक हैं। क्योंकि बीडी शर्मा पहले से ही अतिरिक्त कार्यकाल पर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कितने दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से पर्दा उठता है।

कांग्रेस नेतृत्व ने बघेल को किया तलब



छत्तीसगढ़ कांग्रेस से खबर है कि पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली तलब किया है। बघेल को दिल्ली तलब करने के पीछे क्या कारण है यह अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन बघेल करीबियों के अनुसार पिछले दिनों हुई ईडी और आयकर विभाग की कार्यवाही में जो तथ्य निकलकर सामने आये हैं उससे आलाकमान बहुत नाराज है, क्योंकि बघेल के करीबियों ने पूछताछ में पार्टी आलाकमान के कई शीर्षस्थ नेताओं के नाम ले लिये हैं जिनसे आगामी समय में ईडी और आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बघेल इस पूरी समस्या से किस तरह से छुटकारा पाते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से बघेल के सितारे गरदश में समझ दिखाई पड़ रहे हैं।

हपते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

हायरस रेप पीड़ित के परिवार को घर में बंद करके रखना और गैंग रेप के आरोपियों को सुलेआम घुलना बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

BJP सरकार ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा भी पूरा नहीं किया है।

-राहुल गांधी

काबोल नेता @RahulGandhi



मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। महिलाएँ, बच्चे, किसान और गोजवान सभी परेशान हैं। दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। महंगाई परम पर है।

लेकिन इस सब से भाजपा की सरकार को कोई मतलब नहीं है।

-कमलनाथ



प्रेत कब्रों अजब
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

गांधी परिवार के एक और सदस्य प्रियंका गांधी की संसद के परिसर में हुई आमद

समता पाठक/जगत प्रवाह



प्रियंका गांधी एक भारतीय राजनेता, कांग्रेस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की पोती हैं। वह अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं और अक्सर प्रियंका गांधी की तुलना दादी-माँ के साथ की जाती है। उन्होंने अपना पहला भाषण 16 साल की उम्र में ही दे दिया था, जिससे यह पता चलता है कि उनके अंदर नेता की गुणवत्ता अंतर्निहित है और यह वंशानुगत है। जैसा कि हम जानते हैं कि वह 2019 तक राजनीति में वे ज्यादा सक्रिय नहीं थीं। होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत कर रही है। इसी के कारण कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के एआईएससी के जनरल सेक्रेटरी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रियंका गांधी या प्रियंका गांधी वाड़ा का जन्म 12 जनवरी, 1972 को नेहरू-गांधी परिवार में हुआ था। वह राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी हैं। उनके पिता भारत के प्रधानमंत्री थे और माँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रियंका गांधी के भाई हैं। वह अपने भाई राहुल गांधी से दो साल छोटी हैं। उन्होंने 18 फरवरी, 1997 को एक व्यवसायी रॉबर्ट वाड़ा से शादी की और रेहान और मिरया 2 बच्चों की माँ हैं।

संजय गांधी उनके चाचा थे जिनकी 1980 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और मेनका गांधी उनकी चाची हैं और दक्षिणपंथी राजनीतिक दल, भाजपा की एक राजनेता और महिला और बाल विकास की केंद्रीय वैबिनेट मंत्री हैं। वरुण गांधी प्रियंका गांधी के चचेरे भाई और भाजपा के एक राजनीतिज्ञ हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा मॉडर्न स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी, नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने 2010 में साइकोलॉजी विषय में स्नातक और फिर बी.एड. अध्ययन में एम.ए. किया। प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो वह जनवरी 2019 तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं, लेकिन वह अमेटी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। 2004 में, वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी माँ के अभियान की प्रबंधक थीं। उन्होंने 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमेटी-रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद की। लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें 23 जनवरी, 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है। 16 साल की उम्र में प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था जो कि एक नेता की विरासत की गुणवत्ता को दर्शाता है।

मिसाल

एआई, चैट जीपीटी और तकनीक से ग्रामीणों को जोड़कर आईएसएस अधिकारी जयंत नाहटा ने पेश की मिसाल



प्रशासनिक सेवा के दायित्व के साथ सामाजिक सेवा को प्राथमिकता में रख जयंत नाहटा ने बदली छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले की तकदीर और तस्वीर

-विजया पाठक

कहते हैं वजन में अगर सच्ची लगन और इच्छाशक्ति से तो नेक मन से किए गए कार्यों को पूरा करने में चाहे जितनी चुनौतियाँ आ जाएं वह आपके इरादे इतना मजबूत कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ नेक इरादों के साथ प्रशासनिक सेवा में आए आईएसएस अधिकारी जयंत नाहटा। वर्ष 2020 बैच के आईएसएस अफसर जयंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के नक्सली क्षेत्र में बतौर जिला पंचायत सीईओ के पद पर पदस्थ हैं। मूलतः पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जयंत के मन में कॉलेज के दिनों से ही छोटे और कमजोर वर्ग के बच्चों और महिलाओं को शिक्षित करने का भाव था यही कारण है कि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जयंत ने शासकीय सेवा के साथ सामाजिक सेवा का दायित्व भी बखूबी निभाया और उन्होंने दंतेवाड़ा के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं की दशा और दिशा बदलने का कार्य आरंभ किया। जयंत की पहली पॉस्टिंग वर्ष 2021 में दंतेवाड़ा में बतौर एसडीएम हुई थी। उन्होंने ड्यूटी गंवाइन करते ही गिने व गिनाएँ किया और सामाजिक समस्याओं के अलावा उन्होंने जिले की व्यावहारिक समस्याओं को करीब से देखा और उसे समाधान के बाद इस समस्या के निदान की दिशा में कार्य आरंभ किया।

पढ़ाई को बनाया रुचिकर

जयंत ने बच्चों को स्कूल और किताबों से जोड़े रखने के लिए पढ़ाई को रुचिकर बनाया। बच्चे अब बैग लेकर नहीं बल्कि एआई की मदद से टेबलेट तथा स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए वे जिले में हर स्कूल में दो घंटे की एआई क्लास लगाते हैं। अब बच्चे एआई मॉडल से सबाल पूछते हैं और साथ ही भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भी सीख रहे हैं।

तकनीक से आसान बना इलाज

जयंत ने ग्रामीणों के इलाज के लिए एआई तकनीक का उपयोग कर एक वर्चुअल नर्स की मदद लेना आरंभ किया। चैट जीपीटी से तैयार हेल्थ असिस्टेंट मॉडल में 5 साल हैं। ड्रम-जेंडर, लक्षण, जांच, इलाज और लाइफ स्टाइल चेंज। इससे ही नर्स इलाज कर पा रही हैं।

फोन पर मिलता है उपचार

जयंत ने ग्रामीणों के लिए ऑनलाइन डॉक्टर की व्यवस्था की जिससे ग्रामीणों को आवश्यकता पड़ने पर छोटी बीमारियों का इलाज तुरंत मिल जाए जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर कैमरे और कंप्यूटर लगाए गए हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की 3 घंटे ड्यूटी लगती है। वे वीडियो कॉल से रोज 100 का इलाज करते हैं।

इलाज की व्यवस्था

जयंत ने ग्रामीणों के लिए त्वरित उपचार की व्यवस्था की और गांव के लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं होता है अब गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है।

जटिलताओं के उद्भव से भी जुड़े रहे

जयंत नाहटा ने अपने जिला प्रशिक्षण के दौरान अमूल्य अंतर्दृष्टि सीखी, भले ही कई अन्य लोगों को अपने प्रशासनिक प्रशिक्षण के दौरान संपर्क करना पड़ा। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को निखारने के साथ-साथ, उनके अनुभव जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे विवाह और व्यवस्था की जटिलताओं के उद्भव से भी जुड़े रहे। सिविल सेवा प्रशिक्षण से गुजरने की कठिनाइयों के बीच, जयंत की राह भावनात्मक और पेशेवर दोनों तरह से विकास की एक दिलचस्प कहानी है। कोलकाता में पैदा हुए और पले-बढ़े होने के बावजूद, जयंत की जड़ें दिल्ली के



यूपीएससी केंद्र, ओल्ड राजेंद्र नगर में गहराई से जमी हुई थीं, जहां वह ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो सिविल सेवाओं में काम करने की इच्छा रखते थे। जब वह दो साल के थे, तब उनके माता-पिता दिल्ली आ गए, उनके शैक्षणिक पथ में 2013 में एक नाटकीय बदलाव आया जब उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने पांच साल तक बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन किया और इस प्रक्रिया में बी.टेक और एम.टेक की डिग्री हासिल की। जब जयंत ने आईआईटी दिल्ली में अपने चौथे वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा

के लिए परिश्रमपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया, तो यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वरिष्ठों से प्रेरित होकर, उन्हें एहसास हुआ कि सिविल सेवाओं में करियर से समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। निर्णय लेने और रचनात्मक परिवर्तन लाने की उनकी प्रवृत्ति छात्र मामलों की परिषद के महासचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान स्पष्ट हो गई थी जब उन्होंने बड़ी सफलता के साथ इलेक्ट्रॉनिक चोटिंग पद्धति शुरू की और प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों का ध्यान आकर्षित किया। हालाँकि, उनकी यूपीएससी यात्रा चुनौतियों से सज्ज थी। अपने पहले प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स और मेन्स

तो पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सके। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और साल 2019 में फिर से कोशिश की, इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 298वीं रैंक के साथ परीक्षा पास की और भारतीय सिविल अकाउंटेंट्स सर्विस में जगह बनाई। हालाँकि, वे यहीं नहीं रुके, उनका सपना आईएसएस बनने का था, इसलिए उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और तीसरी बार फिर से परीक्षा दी। 56वीं रैंक प्राप्त करके, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जयंत नाहटा यकीनन जूनून और जल्द की मिसाल है।

सफलता के तीन स्तंभ: स्वस्थ शरीर, शांत दिमाग और बुलंद इरादे



आज की बात प्रवीण कवकड़ स्वतंत्र लेखक

आज हम बात करेंगे सफलता के उन तीन स्तंभों के बारे में, जिन पर आपकी सारी उपलब्धियां टिकी हुई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूँ स्वस्थ शरीर, शांत दिमाग और बुलंद इरादों की।

स्वस्थ शरीर: सफलता का आधार
एक स्वस्थ शरीर ही आपको उर्जावान बनाए रखता है और आपको मेहनत को सार्थक बनाता है।

शांत दिमाग: सही फैसले का मार्गदर्शक

शांत दिमाग ही आपको सही फैसले लेने और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करते हैं। एक शांत दिमाग आपको तनाव मुक्त रखता है और आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है।

बुलंद इरादे: सफलता का इंजन

एक बुलंद इरादा ही आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और कभी हार न मानें। एक बुलंद इरादा आपको सफलता की ओर ले जाता है और आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है।

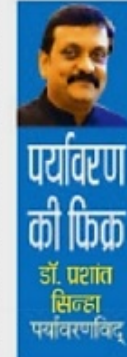
इन तीनों स्तंभों को कैसे मजबूत करें?

- **निश्चित व्यायाम:** रोजाना कुछ समय व्यायाम के लिए निकालें।
- **संतुलित आहार:** पौष्टिक आहार लें।
- **पर्याप्त नींद:** रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें।
- **ध्यान:** रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें।
- **योग:** योगसन आपके शरीर

निष्कर्ष:

स्वस्थ शरीर, शांत दिमाग और बुलंद इरादे सफलता के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन तीनों का संतुलन बनाकर अमूल्य एक सुराहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। आज ही इन तीनों स्तंभों पर काम करना शुरू करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।

अति उपभोग वास्तव में एक वैश्विक संकट है



पर्यावरण की फिक्र डॉ. पराश सिन्हा पर्यावरणविद्

अति उपभोग वास्तव में एक वैश्विक संकट है, जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। हमने तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के जरिए अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और आसान बना लिया है। हमारी आधुनिक जीवनशैली ने हमें हर वह सुविधा दी है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। लेकिन इस प्रगति की एक बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। यह कीमत है अति उपभोग—एक

ऐसी आदत, जो धीरे-धीरे न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी खतरे में डाल रही है। अति उपभोग का सीधा अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों और वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उपयोग। यह केवल हमारे आस-पास के पर्यावरण को नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यदि हम इसे नहीं रोकते, तो इसका प्रभाव इतना गहरा और व्यापक होगा कि मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। अति उपभोग के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है उपभोक्तावाद। आधुनिक समय में सफलता और खुशी को भौतिक वस्तुओं से जोड़ा जाने लगा है। महंगे कपड़े, नए गैजेट, बड़ी कारें, और विलासितापूर्ण जीवनशैली अब केवल विकल्प नहीं हैं, वे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक बन गए हैं। विज्ञापन, सोशल मीडिया, और ब्रांडिंग हमें यह यकीन दिलाते हैं कि जितनी अधिक चीजें हमें खरीदेंगे, उतना ही बेहतर जीवन हमारा होगा। इस अंधाधुंध उपभोग को बढ़ावा देने में कंपनियों और बाजारों की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा, जनसंख्या वृद्धि ने संसाधनों पर दबाव को और बढ़ा दिया है। एक ओर जहां विकासशील देशों की बढ़ती आबादी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं विकसित देश अति उपभोग में डूबे हुए हैं। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने इस समस्या को और बढ़ावा दिया है। शहरों में बढ़ते पैमाने पर निर्माण और ऊर्जा खपत, औद्योगिक कचरे का उत्पादन, और कच्चे माल की मांग ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। अंततः, हम यह समझना होगा कि अति उपभोग केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यह एक नैतिक और सामाजिक चुनौती भी है। यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हम समय रहते नहीं चिंते, तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हमें अपने उपभोग के तरीकों को पुनः परिभाषित करना होगा। एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जो न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और समृद्ध हो। हर छोटी कशिश, चाहे वह ऊर्जा बचाने की हो, कचरे को कम करने की हो, या पेड़ों को बचाने की, एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारे पास अभी भी समय है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने संसाधनों का विक्रेत उपयोग करें और इस संकट को टालने के लिए सामूहिक प्रयास करें। आइए, हम सब मिलकर एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ के साथ चल रही साय सरकार

-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर। सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ के साथ साय सरकार चल रही है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस संकल्प के साथ विकसित भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में भी जनहित कार्यों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता को दोहरा लाभ मिल रहा है। साय सरकार में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता के तीन कार्यस्तंभ के जरिए लोगों तक सुरासन का संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का छत्तीसगढ़ को भरपूर लाभ मिल रहा है। केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने में छत्तीसगढ़ लगातार अग्रणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। जिनमें पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार से पूरे देश में सर्वाधिक 8.46 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे के पात्र 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को भी पक्का मकान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक



पीएम आवास योजना ग्रामीण में 01 लाख 74 हजार 585 हितग्राहियों को उनका आवास मिल चुका है। प्रदेश में पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को पीएम जनमन योजना का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 24 हजार 542 परिवारों को आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा 1 हजार 699 करोड़ की स्वीकृति से 2 हजार 449 किलोमीटर की 715 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनसे 777 पीव्हीटीजी बसाहटें लाभान्वित होंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, इस उपलब्धि के लिए भारत द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य के 266 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी दिया है। छत्तीसगढ़ में 11 लाख 20 हजार से ज्यादा मरीज आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2023 से नवम्बर 2024 तक 883 संविदा पदों पर नियुक्ति भी दी गई है। डबल इंजन की सरकार

में छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार भी डबल हो गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दूरस्थ इलाकों में 103 किलोमीटर लम्बाई की सड़क बन चुकी है, इनमें 616 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य भी जारी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ ही छत्तीसगढ़ के 50 लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 40 लाख परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रूपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। उरगा-कटघोरा बाईपास, बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट और रायपुर-लखनादोन इकॉनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी केन्द्र से स्वीकृति मिल चुकी है, 236.1 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाले इस कॉरिडोर को 9208 करोड़ रूपए की लागत बनाया जाएगा। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 20 हजार करोड़ रूपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री को पहल पर छत्तीसगढ़ को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 240 ई-बसों की स्वीकृति भी मिली है, ये बसें रायपुर, बिलासपुर, कोरवा और दुर्ग-भिलाई में चलेंगी। इस सुविधा से आम लोगों को सस्ती दर में परिवहन की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का दोहरा फायदा पहुंच रहा है, किसान अपनी सुविधा से अधिकतम 5 लाख तक अल्पकालीन कृषि ऋण भी ले सकते हैं। मोदी जी की गारंटी पर मुख्यमंत्री की पहल से छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके धान का देश में सबसे उच्चतम मूल्य मिल रहा है।



सुशासन का साल छत्तीसगढ़ हुआ सुशहल



इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण

- कोरम-विजासमर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण
- मिलान में उद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
- 1 वर्ष में 06 फुटपाथों और 04 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
- औद्योगिक विकास के लिए ₹6,000 करोड़ प्रस्तावित

उद्योगों का उदय

- एक वर्ष में 1,379 उद्योग स्थापित, ₹9,000 करोड़ का निवेश और 28,000+ लोगों को रोजगार
- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू
- 0 जर्नी में 8 जवाब देते रोजगार युवाओं का लक्ष्य
- 27 औद्योगिक समूहों को ₹32,225 करोड़ का निवेश हेतु आग्रह का जवाब
- उद्योगों, प्रजापति, वेला गैर, इको-गैर, इको-गैर, इको-गैर और कोरम-विजासमर जैसे नए क्षेत्रों में विशेष की योजना

आधारभूत औद्योगिक विकास छत्तीसगढ़ बन रहा औद्योगिक हब

- हाफेस्ट छत्तीसगढ़ आभियान हेतु 40 करोड़ का प्रावधान
- मिलान नीति 2.0 एक नए आयोजन पर सभी किसानों से कर्मीस
- उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, अहमदाबाद और भारत कलेक्ट्रेट के साथ परामर्श
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सहायता परियोजना का गठन

हमारी संस्कृति हमारी पहचान

राज्यीय युवा समीक्षा
जुलाई से अक्टूबर तक आयोजित

राज्यीय कला प्रतियोगिता
कला, साहित्य, नृत्य, संगीत और अन्य क्षेत्रों में आयोजित

राज्यीय खेल प्रतियोगिता
खेल क्षेत्रों में आयोजित

नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

- राज्यीय युवा समीक्षा
- राज्यीय कला प्रतियोगिता
- राज्यीय खेल प्रतियोगिता
- राज्यीय अर्थोद्योग प्रतियोगिता
- राज्यीय अर्थोद्योग प्रतियोगिता
- राज्यीय अर्थोद्योग प्रतियोगिता

महिला शक्ति को मिला सम्मान और सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक पहले

महिला शक्ति को मिला सम्मान और सुरक्षा

- 20 लाख महिलाओं और बच्चों को ₹1000 प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता
- अब तक ₹400 करोड़ का प्रस्तावित

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

- राज्यीय स्तर पर 10 लाखों को ₹50,000 की आर्थिक सहायता
- कोटी के विवाह में मदद और अर्थोद्योग का प्रस्ताव

महिलारी सदन योजना

- ₹44.21 करोड़ में 200 सदन
- प्रादेशिक स्तर पर 175 सहायता सदन

नारी शक्ति को सम्मान

- बी के एम ए कोरम-विजासमर
- विजासमर कोरम-विजासमर
- विजासमर कोरम-विजासमर
- विजासमर कोरम-विजासमर

भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम

राज्य होगी आज जनता को चलते-चलते भ्रष्टाचार के विरुद्ध जग से रहेगी **अर्थोद्योग** को नीति

भ्रष्टाचार के काले अंधकार पर प्रहार से आरम्भ समृद्धि यज्ञों के परिवर्तन में **पारदर्शिता** से होगी **पारदर्शिता**

शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता

- राज्य सेवा परीक्षा-2024 की निष्पत्ति और परामर्शी जग
- सूचीबद्धों की लगे पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय

घोटालों पर सरकार की सख्ती

राज्यीय स्तर पर 2024 तक ₹200 करोड़ के परियोजना पर 100% की निष्पत्ति

सूचीबद्धों पर भ्रष्टाचार पर 100% की निष्पत्ति

युवाओं का भविष्य अब होगा और भी उज्वल

राज्यीय युवा समीक्षा, राज्यीय कला प्रतियोगिता, राज्यीय खेल प्रतियोगिता, राज्यीय अर्थोद्योग प्रतियोगिता

मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक कदम अन्नदाना के समृद्धि लिए

जल संसाधन से मछुवारों की समृद्धि

राज्यीय स्तर पर 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान

किसानों को बोनस

- 2 लाख का बकाया धान बोनस
- 13 लाख किसानों को ₹3,716 करोड़ का बोनस

किसानों को विरोध ऊर्जा से प्रशिक्षण सुविधा

- 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान
- 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान

सैन्यवालय उपायवायव्य भूमिहीन युवा भोजन योजना

- ₹ 10,000 की वार्षिक आर्थिक सहायता
- ₹ 500 करोड़ का बजट प्रावधान

कृषक उन्नति योजना

- ₹ 100 करोड़ का प्रावधान
- ₹ 100 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

राज्यीय स्तर पर 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान

राज्यीय स्तर पर 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान

राज्यीय स्तर पर 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान

नक्सल उन्मूलन एवं जनजातीय उत्थान

नियत नेल्ला नार

राज्यीय स्तर पर 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान

जनजातीय उत्थान

राज्यीय स्तर पर 10 लाखों को 100 करोड़ का प्रावधान

RO No : 13057/195